

## Padma Bhushan



### SHRI NRIPENDRA MISRA

Shri Nripendra Misra is a career civil servant who joined the Indian Administrative Service (IAS) in 1967 and was allotted the Uttar Pradesh (UP) Cadre. He has served the nation for 54 years in various strategic positions of the Governments of UP and India, including the Principal Secretary to Prime Minister Shri Narendra Modi and the Chairperson of the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). He is currently the Chairperson of the Construction Committee of the Shri Ram Janmabhoomi Mandir Trust. He is also the Chairperson of the Executive Council of Nehru Memorial Museum and Library.

2. Born on 8<sup>th</sup> March, 1945, Shri Misra holds Post-Graduate degrees, with distinction and rank, in both Chemistry and Political Science from the University of Allahabad. He joined public service in 1967, at the age of 22 years. The early years of Independence shaped his ideals to devote himself to the Indian polity. The increasing focus of development economics in a growing nation convinced him to earn his third Masters' Degree in Public Administration at Harvard University in 1980-81.

3. Shri Misra's work, early in his career, was acknowledged in 1971 when he was conferred with the Best Officers' Award by the Government of UP. The Award, while recognizing excellence in implementing Government policy at the district level, was particular in commending his contribution to food safety and wheat procurement. He enabled farmers' welfare as Chairperson of the Land Development Bank and Provincial Cooperative Federation in UP. His efforts in revamping cash strapped cooperatives through reorganization of societies and effective recovery of credit through a cheque system was lauded by the Reserve Bank of India. His deep insights in cooperative credit and financial sectors were acclaimed in his consultancy assignments for the Asian Development Bank, the International Fund for Agricultural Development, and by the Governments of Nepal and Bangladesh. As Principal Secretary (Finance) of Uttar Pradesh, he initiated treasury computerization, structured excise and taxation policies, and established zero-based budgeting. The foundation of the flourishing township of Greater Noida was conceptualized under his chairmanship. He actively participated in sensitive law and order issues during communal disturbances in Uttar Pradesh.

4. Shri Misra was assigned international trade in the Ministry of Commerce, Government of India and led negotiating teams to the European Union and the World Trade Organization (WTO). With an emphasis to build exports by medium and small-scale sectors, he assiduously worked in moderating inequitable tariff and non-tariff barriers. As Joint Secretary, Multi-Lateral Institutions, he ensured successful outcomes between India and external aid agencies. This commitment was heightened when, as Additional Secretary, WTO, he made significant contributions to benefit the nation in the crucial Doha round of trade talks. His stint as the Union Fertilizers Secretary was marked by improved transparency in pricing of these items. His leadership in the Telecom sector has had lasting impact on the mobile users of India. As Union Telecom Secretary, he addressed policies of affordability, fair competition, and access. Later, as the Chairman of TRAI, he ensured that rapidly changing technology provided consumers with adequate choice, viable tariff plans, and high quality of service. Further, he fostered an open environment by extending opportunity to stakeholders to participate in decision making. During the period 2009-2013, he floated the Public Interest Foundation, an NGO committed to reinforcing democratic traditions of the country. Through a PIL, the NGO took up the cause of electoral reforms and the apex Court delivered favorable judgment striking at the root of criminalization in politics.

5. Shri Misra's dedication to public welfare received extraordinary recognition when he was selected as the Principal Secretary to Prime Minister Modi. In his tenure between 2014 to 2019, he dedicated himself to the PM's vision and aligned patriotism with astute political decisions and policy making to empower the common man. He enabled the Jan Dhan Yojana, reaching gas cylinders to rural women, national healthcare program Ayushman Bharat, revamping the purchasing power of farmers and major economic reforms including Goods and Services Tax (GST). Elevated to the equivalence of Cabinet Minister in 2019, he strengthened the hands of the Prime Minister in ushering the rise of a bold, growing, and immensely capable India. He considers serving India in his smallest and biggest capacity as a tremendous privilege, a loan he continues to pay back to his motherland. He counts the innumerable people he has had the opportunity to assist as his biggest award.



### श्री नृपेन्द्र मिश्र

श्री नृपेन्द्र मिश्र एक लोक सेवक हैं, 1967 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के लिए हुआ और उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष सहित उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर 54 वर्ष तक राष्ट्र की सेवा की है। वर्तमान में वह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। वह नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी हैं।

2. 8 मार्च, 1945 को जन्मे श्री मिश्र ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान और राजनीति विज्ञान दोनों में विशेष योग्यता और रैंक के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की हैं। उन्होंने 1967 में, 22 साल की उम्र में लोक सेवा ज्वाइन की थी। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में, भारतीय राजनीति के प्रति स्वयं को समर्पित करने के लिए उनके आदर्शों को नया आकार मिला। एक प्रगतिशील राष्ट्र में विकास के अर्थशास्त्र पर बल दिए जाने के कारण, वह 1980-81 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन में अपनी स्नातकोत्तर की तीसरी डिग्री अर्जित करने के लिए प्रेरित हुए।

3. नौकरी की शुरुआत में, 1971 में श्री मिश्र के काम को उस समय प्रशंसा प्राप्त हुई जब उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार जिला स्तर पर सरकारी नीति को लागू करने में उनके कौशल, विशेष तौर पर खाद्य सुरक्षा और गेहूं खरीद में उनके योगदान के फलस्वरूप दिया गया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भूमि विकास बैंक और प्रांतीय सहकारी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसानों के कल्याण के लिए कार्य किया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समितियों के पुनर्गठन और चेक प्रणाली के माध्यम से ऋण की बेहतर वसूली के माध्यम से नकदी की तंगी वाली सहकारी समितियों को दुरुस्त करने के उनके प्रयासों की सराहना की गई। सहकारी ऋण और वित्तीय क्षेत्रों में उनकी गहरी अंतर्दृष्टि और एशियाई विकास बैंक, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में उनके परामर्श कार्यों की नेपाल और बांग्लादेश की सरकार द्वारा प्रशंसा की गई। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव (वित्त) के रूप में उन्होंने ट्रेजरी कंप्यूटरीकरण, संरचनाबद्ध आबकारी और कराधान नीतियों की शुरुआत की और शून्य बजटिंग की स्थापना की। ग्रेटर नोएडा की शानदार टाउनशिप की संकल्पना उनकी अध्यक्षता के दौरान ही की गई थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक उपद्रव के दौरान कानून व्यवस्था के संवेदनशील मुद्दों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

4. श्री मिश्र को, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार सौंपा गया और उन्होंने यूरोपीय संघ और विश्व व्यापार संगठन में वार्ता दलों का नेतृत्व किया। मध्यम और छोटे क्षेत्रों की निर्यात क्षमता पर जोर देते हुए उन्होंने असमान टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों को कम करने के लिए बहुत काम किया। बहुपक्षीय संस्थानों के संयुक्त सचिव के रूप में, उन्होंने भारत और विदेशी सहायता एजेंसियों के बीच बातचीत के सफल परिणाम सुनिश्चित किए। यह प्रतिबद्धता तब और बढ़ गई जब विश्व व्यापार संगठन के अपर सचिव के रूप में, उन्होंने दोहा में व्यापार वार्ता के महत्वपूर्ण दौर में राष्ट्र को लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। केंद्रीय उर्वरक सचिव के रूप में उनके कार्यकाल में इन मदों के मूल्य निर्धारण में बेहतर पारदर्शिता आई। दूरसंचार क्षेत्र में उनकी अग्रणी भूमिका का भारत के मोबाइल प्रयोक्ताओं पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। केंद्रीय दूरसंचार सचिव के रूप में उन्होंने सस्ती सेवा, ईमानदार स्पर्धा और सुगम्यता की नीतियों पर बल दिया। बाद में, ट्राई के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी में उपभोक्ताओं को पर्याप्त विकल्प, व्यवहार्य टैरिफ योजनाएं और उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्राप्त हो। इसके अलावा, उन्होंने हितधारकों को निर्णय में भाग लेने का अवसर प्रदान करके एक खुले वातावरण को बढ़ावा दिया। 2009-2013 की अवधि के दौरान, उन्होंने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध एक गैर-सरकारी संगठन पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन की शुरुआत की। इस गैर-सरकारी संगठन ने एक जनहित याचिका के माध्यम से, चुनाव सुधार के मुद्दे को उठाया और शीर्ष अदालत ने राजनीति के अपराधीकरण की जड़ पर प्रहार करते हुए अनुकूल फैसला सुनाया।

5. प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव चुने जाने पर लोक कल्याण के प्रति श्री मिश्र की निष्ठा को असाधारण पहचान मिली। 2014 से 2019 के बीच अपने कार्यकाल में उन्होंने आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की संकल्पना तथा सूझबूझ भरे राजनीतिक फैसलों और नीति निर्माण के साथ देशभक्ति को जोड़ने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने जनधन योजना, ग्रामीण महिलाओं तक गैस सिलेंडर पहुंचाने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत, किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने तथा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित बड़े आर्थिक सुधारों को सफल बनाया। 2019 में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने के बाद, उन्होंने एक साहसिक, अग्रसर और अत्यधिक समर्थ उदीयमान भारत के लिए प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत किए। वह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पदों पर रहते हुए भारत की सेवा को अपना सौभाग्य मानते हैं और इसे अपनी मातृभूमि का ऋण मानते हैं, जिसे वह लगातार चुका रहे हैं। वह असंख्य लोगों की मदद का अवसर दिए जाने को अपना सबसे बड़ा पुरस्कार समझते हैं।